सी आइ टी यू जनरल कौंसिल का आह्वान:

नयी आर्थिक नीतियों के विरुद्ध संघर्ष के अगले दौर की तैयारियां करें

□ पी के गांगुली

हावड़ा में 31 मई से 2 जून तक संपन्न सी आइ टी यू जनरल कौंसिल की बैठक ने अपनी सभी राज्य समितियों; जिला समितियों को आह्वान किया है कि वे नरसिम्हा राव सरकार की नयी आर्थिक नीतियों के विरुद्ध सघन एकजुट कार्रवाइयों के आगामी चरण की तैयारियां करें।

आर्थिक नीतियों के विरुद्ध संघर्ष से संबंधित प्रमुख प्रस्ताव कामरेड के एन रविन्द्रनाथ द्वारा प्रस्तुत किया गया जबकि कामरेड एन प्रसाद राव ने उसका अनुमोदन किया। प्रस्ताव में जन संगठनों के राष्ट्रीय मंच के मध्य जुलाई में दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किये जाने और नयी आर्थिक नीतियों के विरुद्ध देशव्यापी कार्रवाई संबंधी कार्यक्रम के आगामी चरण की घोषणा करने से संबंधित निर्णय का स्वागत किया गया। प्रस्ताव में सभी ट्रेड यूनियनों तथा जनसंगठनों से अनुरोध किया गया कि वे पहले से स्थापित एकता को और सुदृढ़ करने तथा दृढ़ निश्चयी संघर्ष की नयी लहर में देश को लाखों लोगों तथा जनतांत्रिक, धर्म निरपेक्ष एवं देशभक्त शक्तियों की लामबंद करें ताकि भारत की आर्थिक स्वतंत्रता को नष्ट करने और उसे अपने दासत्व में लाने के अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष तथा विश्व बैंक के षडयंत्र को जुझारू जन कार्रवाइयों के माध्यम से मुंहतोड़ प्रत्युत्तर दिया जा सके और उसे पराजय दी जा सके।

सी आइ टी यू की पच्चीसवीं वर्षगांठ

जनरल कौंसिल की यह बैठक क्योंकि सी आइ टी यू की पच्चीसवीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की गई थी, इसलिये वह एक महत्वपूर्ण घटना बन गई। बैठक से पूर्व 30 मई को सी आइ टी यू के स्थापना दिवस के अवसर पर कलकत्ता के नेता जी इंडोर स्टेडियम में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री कामरेड ज्योति बसु तथा सी आइ टी यू के अध्यक्ष कामरेड ई० बालानंदन, महासचिव कामरेड एम के पंधे तथा सचिव कामरेड नीरेन घोष इत्यादि नेताओं ने इस जनसभा को संबोधित किया। सी आइ टी यू नेताओं ने संगठन की स्थापना के समय की घटनाओं का स्मरण कराते हुए कहा कि सी आइ टी यू का गठन एक ऐसे वर्गीय संगठन के जन्म की घोषणा थी जो समाजवादी राज्य की ओर अग्रसर होने तथा श्रमिक वर्ग के वर्गीय संघर्ष के प्रति प्रतिबद्ध था। उन्होंने श्रमिक वर्ग के व्यापक भागों की एकजुट करते हुए और एक परिसंघ का गठन करने के माध्यम से ट्रेड यूनियन एकता जिससे सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध एकजुट संघर्षों को और शक्ति मिलेगी, को सुदृढ़ बनाते हुए एकजुट संघर्षों को विकसित करने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान में साम्राज्यवादी शक्तियां श्रमिक वर्ग पर नव औपनिवेशिक हमला कर रही हैं। नेताओं ने नयी स्थिति का उद्धरण देते हुए श्रमिक वर्ग से आह्वान किया कि वे हड़ताल के अपने अधिकार के लिये संघर्ष करें, जनता के हितों के साथ जुड़े राष्ट्रीय मुद्दों में हस्तक्षेप करें। एटक के महासचिव कामरेड ए बी बर्द्धन यू टी यू सी के नेता अशोक घोष ने भी जनसभा का अभिनंदन किया।

अध्यक्षीय भाषण

सी आइ टी यू अध्यक्ष कामरेड ई बालानंदन द्वारा 31 मई को लाल ध्वज लहराने तथा शहीद वेदी पर पुष्पांजलि अर्पित किये जाने के पश्चात् जनरल कौंसिल बैठक का समारंभ हुआ।

अपने अध्यक्षीय भाषण में कामरेड बालानंदन ने सी आइ टी यू के गठन के उद्देश्यों का स्मरण करते हुए संक्षेप में उन संघर्षों पर प्रकाश डाला जो स्वतंत्र कार्रवाइयों और संयुक्त संघर्षों को विकसित करने के लिये पिछले 25 वर्षों में सी आइ टी यू द्वारा चलाए गए ताकि सरकार की श्रमिक विरोधी तथा जन विरोधी नीतियों का प्रतिकार किया जा सके।

साम्राज्यवादी हमलों के बारे में बोलते हुए उन्होंने क्यूबा पर अमरीका द्वारा पिछले 35 वर्षों में थोपी गयी और जारी रखी जा रही आर्थिक नाकेबंदी का उद्धरण दिया और क्यूबा के लिए उदारतापूर्वक सहयोग देने का आह्वान किया जो समाजवाद की रक्षा के लिए दृढ़निश्चयी ढंग से अमरीकी हमले के विरुद्ध लड़ रहा है। उन्होंने जनवादी कोरिया तथ चीन के विरुद्ध अमरीका द्वारा छोड़े गए हमलों की भी चर्चा की।

उन्होंने विकसित पूंजीवादी देशों में गहराते संकट की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि ये देश बढ़ती बेरोजगारी की चपेट में हैं। उनका सकल घरेलू उत्पाद घट रहा है और रोजगार में कमी आ रही है। उन्होंने अपनी बात की पुष्टि के लिए आई सी डी देशों से संबंधित आंकड़े पेश किए। उन्होंने कहा कि अपने संकट से निकलने कि लिए वे अपना बोझ तीसरी दुनिया के देशों पर डालने का प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए ऋणों के मकड़जाल में फंसा रहे हैं। किन्तु इसके साथ ही साथ बाजारों का हथियाने की कोशिश में उनके मध्य व्यानार युद्ध भी तेज हो गये हैं।

भारत में उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के प्रभावों का जिक्र करते हुए बालानंदन ने संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम का उद्धरण दिया जिसका परिणाम उद्योगों की बीमारी तथा उनके बंद होने सार्वजनिक क्षेत्र को समाप्त करने, बेरोजगारी में भारी महंगाई के रूप में सामने आ रहा है। अंधाधुंध ढंग से निजीकरण के मार्ग पर चलने और भारतीय अर्थव्यवस्था

के सभी क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बेरोकटोक प्रवेश के देश में वि-औद्योगीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। यहां तक कि बिजली, दूर संचार वित्त, रक्षा, एअर लाइंस जैसे अर्थव्यवस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों और साथ ही लघु उद्योग क्षेत्र तथा अन्य छोटे-छोटे क्षेत्रों को भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंपा जा रहा है।

राष्ट्रीय स्थिति की चर्चा करते हुए उन्होंने इस खतरनाक स्थिति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जो सांप्रदायिक तथा विभाजक शक्तियों ने देश में उत्पन्न कर दी है। उन्होंने कश्मीर में चरारे-शरीफ को जलाये जाने और भाजपा-शिवसेना जिनकी गुजरात तथा महाराष्ट्र में सरकारे बन गयी हैं द्वारा उत्पन्न किये गये खतरे का जिक्र किया। उन्होंने स्थिति की मांग के अनुसार संगठन को तैयार करने और देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए और सरकार को अपनी आर्थिक नीतियां वापस लेने के लिए विवश कर देने के लिए और सांप्रदायिक तथा विभाजक ताकतों को मात देने के माध्यम देश की एकता तथा अखंडता की रक्षा करने के लिए एकजुट जन संघर्ष विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया।

महासचिव की रिपोर्ट

कामरेड एम के पंधे ने बैठक में महासचिव की रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और सांगठनिक कामों पर विस्तार से विचार किया गया है। राष्ट्रीय स्थिति पर बोलते हुए हुए पंधे ने संक्षेप में उन संघर्षों का वर्णन किया जो नयी आर्थिक नीतियों के विरुद्ध सी आइ टी यू ने चलाये हैं और दूसरी सभी ट्रेड यूनियों तथा जनसंठनों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय मंच के झंडे तले इन संघर्षों को व्यापक एकजुट संघर्षों के रूप में विकसित किया है जिनमें अखिल भारतीय हड़ताल की कार्रवाइयां भी शामिल हैं। उहोंने आत्मालोचनात्मक ढंग से इन संघर्षों विश्लेषण किसा और सभी दुर्बलताओं से उभरने का आह्वान किया। उन्होंने संसद पर 5 अप्रैल 1994 की ऐतिहासिक रैली 3 से 9 अगस्त तक देश भर में आयोजित विरोध सप्ताह, अखिल भारतीय रेल रोको कार्यक्रम, वामपंथी पार्टियों द्वारा चलाये गये नागरिक अवज्ञा आंदोलन और 29 सितंबर की हड़ताल का विशेष रूप से वर्णन किया। उन्होंने इस्को (आइ आइ एस ओ) के निजीकरण के विरुद्ध एकजुट हड़ताल जिसमें इंटक और बी एम एस भी शामिल हुई और निजीकरण के विरुद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों के संघर्ष के घटना विकास का भी संक्षिप्त विवरण दिया। रिपोर्ट में कपड़ा उद्योग में सी आइ टी यू द्वारा विकसित किए गए संयुक्त संघर्ष का वर्णन किया है जिसमें इंटक, बी एम एस तथा एन एल ओ को भी खींचा गया है। इसके साथ ही साथ असंगठित क्षेत्र में सी आइ टी यू द्वारा की गई प्रगति का विवरण रिपोर्ट में दिया गया है। रिपोर्ट में सी आइ टी यू के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, आइ एल ओ तथा सी टी यू सी के साथ उसके सहयोग और आइ एल ओ के सहयोग और आइ एल ओ के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर बालश्रम के खात्मे के लिए सी आइ टी यू द्वारा लिए गए प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया गया है।

रिपोर्ट में विशेष रूप से संगठन पर जोर दिया गया है और आतमालोचनात्मक ढंग से अन संगठनात्मक कामों को पूरा करने की दिशा में किए गस प्रयासों का विश्लेषण किया गया है जो सी आइ टी यू द्वारा तैयार की गयी संगठन संबंधी रिपोर्ट द्वारा निर्धारित किए गए हैं। कामरेड पंधे ने सी आइ टी यू की सदस्यता इस वर्ष के अंत तक 30 लाख तक पहुंचाने और हिंदी क्षेत्र में संगठन को विकसित करने तथा संगठन के सभी स्तरों पर जनतांत्रिक कामकाज सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने ट्रेड यूनियन एकता पर बल दिया और एक परिसंघ के गठन के लिए अभियान चलाने का आह्वान किया। रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल की नयी औद्योगिक नीति कपर चर्चा की गयी और उसके प्रति समर्थन व्यक्त किसा गया। उन्होंने सांप्रदायिक शक्तियों के खतरे की ओर ध्यान आकृष्ट किया और इनके विरुद्ध दृढ़निश्चयी संघर्ष चलाने का आह्वान किया।

कामरेड सरोज मुखर्जी ने सम्मेलन में कोषाध्यक्ष की रिपोर्ट प्रस्तुत की। एस देव राय तथा तपनसेन द्वारा क्रमशः बीमार औद्योगिक इकाइयों तथा निजीकरण पर दो अन्य रिपोर्टें भी प्रस्तुत की गयी। रंजीत बसु ने बी टी आर ट्रस्ट फंड पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

रिपोर्टों पर बहस

महासिचव की रिपोर्ट पर हुयी बहस में 30 साथियों और औद्योगिक बीमारी तथा निजीकरण से संबंधित रिपोर्टों पर हुयी बहस में 17 साथियों ने भाग लिया। तथापि अध्यक्षीय भाषण और महासचिव की रिपोर्ट ने विचार-विमर्श की दिशा पहले ही निर्धारित कर दी थी जिनमें आर्थिक नीति संघर्षों को आगे बढ़ाने की बात कही गयी थी। सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों के अनुभवों का जिक्र करते हुए बतयाया कि उद्योगों में संरचनातमक समायोजन कार्यक्रम के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। उन्होंने उद्योग बंदियों का वर्णन किया और बताया कि कैसे औद्योगिक इकाइयों को समाप्त करने की धमकी देकर मजदूरों पर जबर्दस्ती स्वैच्छिक सेवानिवृत्त थोपी जा रही है। उन्होंने संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम के चलते होने सपली उद्योग बंदी तथा बीमारी पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इनके कारण हजारों रोजगार समाप्त हो रहे हैं जिसने बेरोजगारी की स्थिति को, जो पहले ही खतरनाक सीमा तक पहुंच चुकी है, और भी भयानक बना दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाइयों का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि कामकाजी पूंजी और कच्चे मालों की पूर्ति रोके जाने के माध्यम से जानबूझकर इन उद्योगों को बीमार बनाया जा रहा है। उन्होंने बी आइ एफ आर के अपने अनुभवों के बारे में बताया जिसमें बीमार उद्योगों को पुनर्जीवित करने की उन सर्वसम्मत योजनाओं को स्वीकार करने से भी कार कर दिया जिन्हें सभी यूनियानों और प्रबंधनो ने संयुक्त रूप से तैयार किया था। उन्होंने लाभ देने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में विनिवेशीकरणश के लिए उठाये जा रहे कदमों का वर्णन करते हुए बताया कि निजी पार्टियों को मामूली कीमत पर इन इकाइयों के शेयर बेचे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों ने वेतन संशोधित करने की मांगें ठुकरा दी हैं, उन्होंने दीर्घावधि से चले आते बोनस, पेंशन और महंगाई भत्ते की किश्तों से संबंधित मुद्दों को न निपटाने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने प्रबंधनों में तथा सरकार में उच्च स्तर पर व्याप्त भयानक भ्रष्टाचार का भी वर्णन किया।

कामरेड पंधे ने ट्रेड यूनियन गतिविधियों के प्राथमिक स्वरूपों तक पर बढ़ते हमलों के अपने अनुभवों के बारे में बताया। उन्होंने विभिन्न

औद्योगिक इकाइयों में अपने संघर्षों के बारे में बताया। और उन समस्याओं का भी वर्णन किया जो कुछ ट्रेड यूनियनों के असहयोग के चलते संयुक्त संघर्षों को विकसित करने में आती है।

विशेष रूप से निजीकरण के प्रश्न पर सदस्यों ने सरकार की नति की आलोचना की। सदस्यों ने दूरसंचार, बिजली, वित्त और एअरलाइंस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के निजीकरण के सिलसिले में गहरी चिंता को व्यक्त किया और इसके विरुद्ध कड़ा संघर्ष चलाने के अपने दृढ़निश्चय को अभिव्यक्त किया।

उन्होंने असंगठित क्षेत्र से संबंधित समस्याओं पर विशेष रूप से जोर दिया और बताया कि कैसे संगठित क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा है और असंगठित क्षेत्र और घरेलू उद्योग में इन उत्पादों को ले जाया जा रहा है, जहां मजदूरों का भयानक शोषण किया जा रहा है। असंगठित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों ने इस क्षेत्र में भी बढ़ती उद्योग बंदी तथा बेकारी के बारे में बताया और बताया कि मजदूर, जिनमें ज्यादातर कामगार महिलाएं है, बहुत भयानक हालात में काम करने पर विवश हैं। कोई मानक न्यूनतम वेतन कोई श्रम कानून या सामाजिक सुरक्षा उपाय न होने के चलते इस क्षेत्र में जंगल का राज चल रहा है। वेतन तो गरीबी की रेखा के नीचे वाले दिये जा रहे हैं जबकि सभी वस्तुओं के मूल्य इतने अधिक हैं कि विशेष रूप से इस क्षेत्र के मजदूर उनमें बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।

इन तीन रिपोर्टों, महासचिव की रिपोर्ट और उद्योगों की बीमारी तथा निजीकरण से संबंधित अन्य दोनों रिपोर्टों को समृद्ध बनाने के लिए सदस्यों ने बहुमूल्य सुझाव दिए। इस बहस में सदस्यों का प्रमुख बल उद्योगबंदी, बीमारी, निजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र को तथा आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के षड्यंत्रों, बेरोजगारी और महंगाइ पर केंद्रित रहा। उन्होंने संघर्ष को और तेज करने के अपने दृढ़निश्चय को व्यक्त किया।

संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम से संबंधित अपने अनुभवों का वर्णन करने के साथ ही साथ उन्होंने सांप्रदायिक शक्तियों के अपने अनुभवों के बारे में भी बताया। महाराष्ट्र, गुजरात तथा उत्तर प्रदेश समेत उत्तरी राज्यों के सदस्यों ने इस समस्या का विशेष रूप से वर्णन किया और इन विभाजक शक्तियों के विरुद्ध अपने संघर्षों की जानकारी दी।

उन्होंने ट्रेड यूनियन एकता को और सुदृढ़ करने और सभी बाधाओं से उबर कर इसे आगे बढ़ाने और इसे एक परिसंघ के गठन तक ले जाने के अपने संकल्प को व्यक्त किया। उन्होंने जन संगठनों के राष्ट्रीय मंच के एक राष्ट्रीय सम्मेलन अयोजित करने के फैसले का स्वागत किया और देशव्यापी हड़ताल समेत कार्रवाई के कार्यक्रम को और तेज करने का सुझाव दिया।

संगठन के संबंध में भी सदस्यों ने मूल्यवान सुझाव दिए और इसे नयी चुनौतियों का सामना करने योग्य बनाने के लिए तैयार करने के अपने संकल्प को व्यक्त किया।

कामरेड एम के पंधे द्वारा बहस का जवाब दिये जाने के बाद कुछ संशोधनों के साथ तीनों रिपोर्टों को स्वीकार कर लिया गया।

सी आइ टी यू की 25वीं वर्षगांठ मनाये जाने से संबंधित एक अन्य प्रस्ताव आर उमानाथ ने प्रस्तुत किया जिसका समर्थन नीरेन घोष ने किया। बैठक ने प्रस्ताव कमेटी द्वारा प्रस्तुत किए गए अन्य अनेक प्रस्तावों को अंतिम रूप देने का अधिकार सेक्रेटेरियट को दिया जिन्हें जनरल कौंसिल द्वारा स्वीकार प्रस्ताव माना जायेगा। इन प्रस्तावों में दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के असंगठित तथा इंजीनियरिंग क्षेत्र की 24 जून की हड़ताल को समर्थन देने संबंधी प्रस्ताव, भारतीय पेटेंट कानून में संशोधन के खिलाफ एफ एम आर ए आइ द्वारा २० जून को की जा रही हड़ताल को समर्थन देने संबंधी प्रस्ताव किसान संघर्षों के साथ एकजुटतता संबंधी प्रस्ताव, हरियाणा की एक पटाका फैक्टरी में हाल ही में हुए विस्फोट से संबंधित प्रस्ताव, एकता से संबंधित प्रस्ताव और वित्तीय क्षेत्र से संबंधित प्रस्ताव इत्यादि शामिल हैं।

ए आइ आइ ई ए के सुंदरम, एफ एम आर ए आइ के डी पी दुबे, ए सी ई यू के आर रामनाथन ने बैठक का अभिनंदन किया। उन्हें इस बैठक के लिए विशेष रूप से नियंत्रित किया गया था।

बी टी आर ट्रस्ट फंड के लिए राजस्थान ने दो लाख रु०, पश्चिम बंगाल ने सवा आठ लाख रुपये और कर्नाटक ने 17,००० रु० का योगदान दिया है। क्यूबा एकजुटता फंड के लिए राज्यों का कोटा तय किया गया है जो 19 दिसंबर 1995 तक पूरा कर लिया जायेगा।

बैठक के निर्णय

1. बैठक ने जुलाई के मध्य में दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के जनसंगठनों के राष्ट्रीय मंच के फैसले को अपना समर्थन दिया। इस सम्मेलन में नयी आर्थिक नीति के विरुद्ध देशव्यापी कार्रवाई के कार्यक्रम के आगामी चरण की घोषणा की जायेगी।

2. बैठक ने सुझाव दिया कि उद्योगों की बीमारी, कामबंदी और निजीकरण पर प्रस्तावित अखिल भारतीय सम्मेलन सिंतबर के पहले सप्ताह में दिल्ली में आयोजित किया जाये। इस संबंध में सी आइ टी यू, इंटक सहित अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से भी संपर्क करेगी।

3. सी आइ टी यू बोनस, महंगाई भत्ते तथा पेंशन संबंधी मुद्दों पर 5 जुलाई को अखिल भारतीय दिवस मनायेगी।

4. बैठक ने मछली पालन पर एक संयुक्त कन्वेंशन आयोजित करने का सुझाव दिया जो नवंबर में कोचीन में आयोजित की जायेगी।

5. बैठक ने सेक्रेटेरियट के इस निर्णय को अपनी स्वीकृति प्रदान की कि सी आइ टी यू की पच्चीसवीं वर्षगांठ ३० मई से शुरू करके तीन महीने तक पूरे देश में निम्नलिखित ढंग से मनायी जाये:

[अ] इन तीन महीनों में सी आइ टी यू की उपलब्धियों को बताते हुए प्रदर्शन तथा जनसभाएं आयोजित की जाये।

[ब] ट्रेड यूनियन एकता और परिसंघ की अवधारणा पर और साथ ही साथ गुप्त मतदान के जरिये ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने के प्रश्न पर संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, सिपोजियमों तथा ट्रेड यूनियन कक्षाओं का आयोजन किया जाय।

[स] व्यापक स्तर पर सी आइ टी यू यूनियनों की सदस्यता बढ़ाने, केंद्र को संबद्धता फीस भुगतान करने और राज्यों को लेवियां देने के लिए सघन अभियान चलाया जाये।

[द] सी आइ टी यू पत्रिकाओं तथा प्रकाशनों की बिक्री बढ़ाने तथा

(शेष पेज 14 पर)

भारत सरकार की नयी आर्थिक नीतियों के विरुद्ध संघर्ष सम्बन्धी प्रस्ताव

सी आइ टी यू जनरल कौंसिल की हावड़ा में 31 मई से 2 जून 1995 तक आयोजित बैठक पिछले चार वर्षों से भारत सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों के परिणामस्वरूप भारतीय जनता की दिन-प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही जीवन स्थितियों पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त करती है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा विदेशी पूंजी को अनेक सुविधाएं तथा छूटें प्रदान की गई हैं। इसके परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था पर उनके पंजे की जकड़ और मजबूत हो गई है। गैट समझौता जिस पर भारत सरकार ने हस्ताक्षर किये हैं, हमारे राष्ट्रीय हितों के विपरीत जाता है। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था के आत्मनिर्भर विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ा है और देश की सम्प्रभुता को क्षति पहुंची है। गैट समझौते का अनुपालन करने के चक्कर में भारतीय एकस्व अधिनियम में संशोधन करने के रूप में भारत सरकार द्वारा एक और विश्वासघाती कदम उठाया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा विश्व व्यापार संगठन के निदेश अब हमारे लिये नित्य प्रतिदिन की बात बन चुके हैं।

उदारीकरण की नीति रूपी बीन की स्वर लहरियों से मस्त मूल्य वृद्धि का अजगर अपना फल फैला कर झूमने लगा है। उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में निर्बाध वृद्धि होने से जन साधारण तथा विशेष रूप से ग्रामीण जनता के जीवन पर भारी दुष्प्रभाव पड़ा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के शनै शनै धाराशायी होने और भूमि सुधारों की कमी के चलते जन साधारण तथा गरीब किसान जनता के कष्टों-कठिनाईयों में अपार वृद्धि हुई है। सरकारी दावों के विपरीत इन नीतियों के परिणाम स्वरूप गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की सेना और भी विशालकाय हो गई है।

आयात शुल्कों में भारी कमी होने तथा भारतीय वस्तुओं के उच्चतर निर्यात शुल्क के कारण भारतीय उद्योगों पर विषय दुष्प्रभाव पड़ा है। इसके कारण औद्योगिक बीमारी बढ़ी है तथा अनेक इकाईयों के अस्तित्व को ही खतरा उत्पन्न हो गया है। बीमार इकाईयों का बिस्तर गोल करने की सरकारी नीति से उत्साहित होकर बी आइ एफ आर यूनियनों तथा अधिकारी संघों द्वारा इकाईयों को जीवनक्षम बनाने के लिये प्रस्तुत प्रस्तावों के प्रति शुष्क एवं कठोर रुख अपना रहा है। यह काम तथा औद्योगिक इकाईयों में संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत कामबंदी होने के साथ-साथ हजारों श्रमिकों की उनके रोजगार से निकाल बाहर किया जा रहा है।

सरकार की आर्थिक तथा औद्योगिक नीतियां रोजगार सर्जन की अपेक्षा बेरोजगारी उत्पन्न कर रही हैं। इन नीतियों के चलते पिछले चार वर्षों में बेरोजगारी 3.4 करोड़ से बढ़ कर लगभग 5 करोड़ हो गई है। इकाईयों में कामबंदी तथा बीमारी के कारण देश में बेरोजगारी की स्थिति और खराब हो गई है। ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी इसी अवधि में चौंका देने वाली सीमा तक बढ़ गई है और यह लगभग 8 करोड़ तक पहुंच चुकी है।

पूंजी विनिवेश तथा शेयरों को निजी हाथों औने-पौने दामों पर बेच देने के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के विखण्डन का काम जोर-शोर से चल रहा है। इससे देश की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को गम्भीर क्षति पहुंची है तथा अ-उद्योगीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। निजीकरण तथा दूरसंचार, ऊर्जा, वित्तीय क्षेत्र, एयर लाइन्स, रक्षा जैसे अर्थव्यवस्था के अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों के द्वार बहुराष्ट्रीयों के लिये खोल देने का काम निर्बाध रूप से जारी है जिसके कारण देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था संकट में पड़ गई है।

उदारीकरण तथा निजीकरण के लिए अविवेचित अभियान के अन्तर्गत सभी प्रतिबंधों तथा जनता के प्रति जवाबदेही को समाप्त किया जा रहा है। इसका परिणाम सरकार के उच्चतम शिखर तक भारी भ्रष्टाचार के रूप में निकला है। उच्च अधिकारी तथा मंत्री अनेक घोटालों में संलिप्त पाए गए हैं। इस तथ्य ने सारे देश को हिला कर रख दिया है। ये लोग दण्डाभाव की स्थिति में निरंतर भ्रष्टाचार में संलिप्त हो रहे हैं।

विनियमीकरण के कारण क्षेत्रों के असमान विकास की गति तीव्रतर होने से साम्प्रदायिक एवं विखण्डनज शक्तियों को बढ़ावा मिला है जिसके कारण देश की एकता तथा अखण्डता खतरे में पड़ गई है।

जनरल कौंसिल देश की सम्प्रभुता की रक्षार्थ कोष निदेशित आर्थिक नीतियों के विरुद्ध निरंतर संघर्ष करने के लिये श्रमिक वर्ग तथा अन्य सभी जन संगठनों को बधाई देती है। इसी अवधि में उनके द्वारा की गईं चार देशव्यापी हड़तालों, जनसभाओं एवं प्रदर्शनों से उनकी इसी दृढ़ प्रतिज्ञा एवं इच्छा की अभिव्यक्ति होती है कि जब तक आर्थिक नीतियां बदली नहीं जातीं वे अपना संघर्ष निरंतर जारी रखेंगे। श्रमिक वर्ग के इस संघर्ष को स्पष्ट रूप में जनता के विशालतर वर्गों का समर्थन प्राप्त हुआ है क्योंकि इन नीतियों ने जनता के प्रत्येक वर्ग पर अपना दुष्प्रभाव छोड़ा है। ट्रेड यूनियनों और किसानों, खेत मजदूरों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं, बुद्धिजीवियों तथा अन्य व्यवसायी लोगों के संगठनों का जन संगठनों के राष्ट्रीय मंच के तत्वाधान में एकजुट हो जाना इन राष्ट्र विरोधी नीतियों के विरुद्ध जन एकता की एक अभूतपूर्व घटना है। इससे और भी विस्तृत जन कार्रवाईयों के लिये अपार सम्भावनाएं उत्पन्न हो गई हैं।

यह जनरल कौंसिल जन संगठनों के राष्ट्रीय मंच द्वारा मध्य जुलाई में किसी समय दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करने तथा आर्थिक नीतियों के विरुद्ध आंदोलन के नये चरण का श्रीगणेष करने सम्बन्धी निर्णय का स्वागत करती है। सी आइ टी यू का दृढ़ विचार है कि ऐसी जन कार्रवाईयों को विकसित करके ही इन प्रतिगामी नीतियों को भारी पराजय दी जा सकती है।

सी आइ टी यू अपनी राज्य समितियों, जिला समितियों तथा सभी सम्बद्ध यूनियनों को आह्वान करती है कि वे राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा घोषित संघर्ष के कार्यक्रम को कार्यरूप देने तथा संघर्षों को और तीव्रतर करने के लिये क्षेत्रीय तथा स्थानीय स्तर पर तैयारियां एवं पहलकदमियां करें।

सी आइ टी यू सभी ट्रेड यूनियनों तथा अन्य जन संगठनों से अनुरोध करती है कि वे पहले से स्थापित अपनी एकता को और सुदृढ़ करें और देश के हजारों-लाखों लोगों तथा सभी जनवादी, धर्मनिर्पेक्ष एवं देशभक्त शक्तियों को इस दृढ़ संघर्ष के लिये लामबंद करें ताकि भारत की आर्थिक स्वतंत्रता को दासत्व की ओर धकेलने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष-विश्व बैंक के षडयंत्र को जुझारू जन संघर्षों के माध्यम से करारा जवाब दिया जा सके। □

अध्यक्षीय भाषण

प्रिय साथियो,

पिछले वर्ष मार्च में आयोजित सी आइ टी यू के आठवें पटना महाधिवेशन के पश्चात् हमारे अनेक महत्वपूर्ण नेता जो सी आइ टी यू के ऊंचे पदों पर रहे और जिन्होंने हमारे संगठन को सुदृढ़तर बनाने के वृहत कार्य में उत्तरदायित्वों का वहन किया था, हमें विच्छोह दे गए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे अनेक कार्यकर्ता भी हमारे मध्य नहीं रहे हैं। कामरेड एस वाई कोल्हाटकर, कामरेड रोबिन सेन, कामरेड क्षिति बर्मन, कामरेड इंबीची बावा, कामरेड टी एच मोहम्मद, कामरेड विजय मोदक तथा कामरेड निर्मल राय भी इनमें सम्मिलित हैं। आइये, हम उन्हें अपने श्रद्धासुगत अर्पित करें और प्रण लें कि सी आइ टी यू की क्रांतिकारी परंपराओं का पालन करते हुए उसे सुदृढ़ बनाने के लिये उनके द्वारा दर्शाए गए मार्ग पर अग्रसर होते रहेंगे।

हमारा आठवां महाधिवेशन 3-7 मार्च 1994 को पटना में संपन्न हुआ था। वहां हमने विस्तारपूर्वक अपने कार्यों पर विचार किया था और अनेक निर्णय लिये थे। महाधिवेशन द्वारा पारित आयोग के दस्तावेज एक ऐसा अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो बहुआयामी गतिविधियों में हमारा मार्ग दर्शन करता है। महाधिवेशन के पश्चात 24-26 जुलाई को नयी दिल्ली में हमारी वर्किंग कमेटी बैठक हुई। उस बैठक में पटना महाधिवेशन के पश्चात घटित घटनाओं तथा स्थिति की समीक्षा करने के पश्चात प्रमुख रूप से सरकार की आर्थिक नीतियों के विरुद्ध तुरंत छेड़े जाने वाले संघर्ष के कार्यक्रम पर विचार किया गया। वर्किंग कमेटी की इस बैठक में एक और अखिल भारतीय हड़ताल का सुझाव विचारार्थ आया और सभी इकाइयों को निदेश दिया था कि वे अन्य मुद्दों पर काम करने के साथ-साथ इस संघर्ष की तैयारियां करें तथा उसे अत्याधिक सफल बनाएं। अंततः हमारे द्वारा 29 सितंबर 1994 को आम हड़ताल की गई। नयी आर्थिक नीतियों के विरुद्ध श्रमिक वर्ग की यह सबसे बड़ी कार्रवाई थी।

सी आइ टी यू का जन्म

अब हम पुनः अपने संगठन के रजत जयंति समारोहों के मध्य हावड़ा में जनरल कौंसिल बैठक का आयोजन कर रहे हैं। इसलिये, स्वाभाविक ही है कि हम पिछले 25 वर्षों में सी आइ टी यू द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करें। किंतु मैं, इस समय यहां उसकी चर्चा नहीं करूंगा। तथापि हमें श्रमिक वर्ग को शिक्षित करने के उद्देश्य से सार रूप में अपने कार्यों, अपनी उपलब्धियों तथा अपनी विफलताओं पर दृष्टिपात अवश्य करना चाहिये। सेक्रेटेरियट द्वारा यह काम किया जाएगा। तथापि हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एटक को छोड़ने और एक नये संगठन सी आइ टी यू का गठन करने संबंधी हमारा निर्णय पिछले 25 वर्षों के अनुभवों के प्रकाश में निःसंदेह ठीक सिद्ध हुआ है। मैं आपको यह भी बता देना चाहूंगा कि हमने एटक के साथ संबंध विच्छेद करने का निर्णय पूरी स्थिति का सावधानीपूर्वक अवलोकन एवं लेखा-जोखा करने के पश्चात् फिलकतापूर्वक लिया था।

जब संगठनात्मक मामलों तथा नीतियों के प्रश्न पर एटक में मतभेद उत्पन्न हुए तब कामरेड पी० राममूर्ति ने दिसंबर 1966 में आयोजित एटक के बम्बई सम्मेलन में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। सम्मेलन द्वारा उसे पारित कर दिया गया। उसी प्रस्ताव में कहा गया था कि संगठन में एकता लाने तथा यूनियनों के एकीकरण के लिये जनवादी कार्यपद्धति को सुनिश्चित बनाने के साथ-साथ यूनियनों के प्रमुख निकायों के चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर कराए जाएं। ट्रेड यूनियन नेताओं द्वारा उस समय तक किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किये जाएं जब तक यूनियन की कार्यकारिणी तथा साधारण सभा द्वारा उसकी पुष्टि नहीं की जाती। यद्यपि सम्मेलन में इन सुझावों को स्वीकार कर लिया गया तथा एटक के प्रमुख पदों पर विराजमान नेताओं ने उन्हें कार्यरूप देने की आवश्यकता ही अनुभाव नहीं की। इसके विपरीत वे अनेक स्थानों पर राजनीतिक कारणों से यूनियनों के कामों में विघ्न डालते रहे। इसके चलते स्थिति और भी बिगड़ गई। ट्रेड यूनियनों में फूट डालने तथा श्रमिक वर्ग के आर्थिक एवं राजनीतिक हितों के लिये संघर्ष न करने की नीति के कारण एटक निष्प्रभावी होकर रह गया था। एटक द्वारा अपनाई गईं वर्ग सहयोग की नीतियों के चलते वह सरकार की पिछलग्गू बन कर रह गया था। इसलिये हमें 1966 के प्रस्ताव को कार्यरूप नही दिये जाने के विरुद्ध दिसंबर 1969 में आयोजित एटक वर्किंग कमेटी बैठक का बहिष्कार करना पड़ा। क्योंकि उन्होंने भारी संख्या में बड़ी यूनियनों को सम्बद्ध करने से इंकार कर दिया था इसलिये हमें एटक के 26वें सत्र का भी बहिष्कार करना पड़ा। यह सत्र गुंटूर में हुआ था। इन्हीं परिस्थितियों में हम एक नया ट्रेड यूनियन केंद्र बनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिये विवश हुए थे। एटक वर्किंग कमेटी बैठक का बहिष्कार करने वाले साथियों ने कामरेड पी राममूर्ति को एटक जनरल कौंसिल तथा राज्य समितियों के उन सहस्यों की बैठक बुलाने उत्तरदायित्व सौंपा जिन्होंने उसके [एटक] गुंटूर सत्र का बहिष्कार किया था। उन साथियों का सम्मेलन 9-1० अप्रैल, 197० को गोआ में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में 27-3० मई 197० को कलकत्ता में एक और सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया। इस प्रकार कलकत्ता में संपन्न ट्रेड यूनियनों के उसी सम्मेलन में भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र की स्थापना की गई।

सी आइ टी यू भारतीय श्रमिक वर्ग का एक अग्रणी जुझारू संगठन बना है। यह बात मैं पहले ही कह चुका हूं और हमारे अपने अनुभवों से भी यह प्रमाणित हो गया है। सी आइ टी यू देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन की एक एकीकृत शक्ति है। वह उन्हें निरंतर संगठित कर रही है और श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षार्थ बड़े-बड़े संघर्षों को नेतृत्व प्रदान कर रही है। इसलिये जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हममें से सभी लोग अर्थात् सी आइ टी यू के नेता तथा कार्यकर्ता निश्चित रूप से दावा कर सकते हैं कि 1970 के कलकत्ता सम्मेलन द्वारा लिये गए निर्णय पूर्णतया ठीक थे।

क्यूबा

अपनी बात को आगे बढ़ाने से पूर्व, आइये हम अमरीका द्वारा समाजवादी क्यूबा के विरुद्ध जारी रखी जा रही आर्थिक नाकेबंदी के विरुद्ध अपनी आवाज उठाएं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्ताव पारित किये जाने तथा विश्व जनमत के विपरीत होने पर भी अमरीका आर्थिक नाकाबंदी के पंजे को और कस रहा है। वह एक नया कानून बना रहा है ताकि वह उसके माध्यम से अन्य देशों को क्यूबा के साथ संबंध बनाए रखने से रोका सके।

सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोपीय देशों में समाजवाद का पराभव होने के कारण क्यूबा को व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में तथा आयातों के एक बड़े भाग की क्षति झेलनी पड़ी है। अब अमरीका द्वारा आर्थिक नाकाबंदी किये जाने के कारण क्यूबा विश्व के अनेक देशों के साथ मुक्त व्यापार नहीं कर सकता। इसके चलते क्यूबा की जनता को अमानवीय कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। उन्हें खाद्य सामग्री जैसी अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं के अभावों का मुंह देखना पड़ रहा है। क्यूबा की जनता विश्व के विभिन्न देशों की सहायता से इन कठिनाइयों पर नियंत्रण पाने का प्रयास कर रही है। इतनी सारी कठिनाइयां होने पर भी उन्होंने समाजवाद की पताका को ऊंचा उठाए रखा है। उन्होंने घोषणा की है- समाजवाद या मौत। कामरेड फिदेल कास्ट्रो जो हाल ही में आयोजित सामाजिक सम्मेलन में भाग लेने के लिये कोपेनहेगन गए थे, उन्होंने वहां भाषण देते समय अन्य बातों के अतिरिक्त कुछ अधोलिखित बातें भी कहीं थीं जो उल्लेखनीय हैं:

"क्यूबा की आपराधिक नाकाबंदी इसलिये की जा रही है क्योंकि वह अपने शक्तिशाली उत्तरी पड़ौसी का सत्र विचारक नहीं है, सोवियत संघ तथा समाजवादी शिविर के ध्वस्त होने से उसे 70 प्रतिशत आयातों की क्षति झेलनी पड़ी है, इस पर भी अपनी एक भी पाठशाला, वृद्धाश्रम, या शिशु पलना गृह को बंद होने नहीं दिया है। एक गरीब देश होने पर भी वर्तमान में हमारे यहां प्रति व्यक्ति अध्यापकों, डाक्टरों, कला तथा खेल निदेशकों की संख्या विश्व भर में सर्वाधिक है। हमारे यहां शिशु मृत्यु दर जन्म लेने वाले प्रति एक हजार बच्चों में मात्र 10 है: हमारे यहां निरक्षरता नहीं है और मानव जीवन की आनुपातिक वर्ष सीमा 75 वर्षों तक पहुंच चुकी है।"

जैसाकि ऊपर संकेत किया गया है, क्यूबाई जनता को आर्थिक नाकाबंदी तथा अपनी समस्यों पर नियंत्रण पाने के लिये प्रत्येक देश से सहायता की आवश्यकता है। भारत कुछ सीमा तक उनकी सहायता कर रहा है और अब क्यूबा के साथ एकजुटता के लिये राष्ट्रीय समिति ने क्यूबा को डिटर्जेंट्स [अपमार्जकों] की खेम भेजने के लिये धन इकट्ठा करने का अनुरोध किया है। इसके लिये हमारी ट्रेड यूनियनों से भी न्यूनतम 10 लाख रुपये का योगदान डालने का आग्रह किया गया है।

मैं आशा करता हूं कि आपके पास इस कोष के लिये धन एकत्रित करने संबंधी सी आइ टी यू द्वारा प्रसारित अनुरोध पत्र पहुंच गया होगा। अत: साथियो, मेरा अनुरोध है कि इस कोष का संग्रह यथाशीघ्र किया जाए ताकि हम उसे राष्ट्रीय क्यूबा साम्राज्यवाद के विरुद्ध हमारे संघर्ष का एक भाग हैं और इसके साथ ही क्यूबा में समाजवादी व्यवस्था की सहायता करने के हमारे प्रण का एक पक्ष है। हमें कम से कम समय में अपना अधिक से अधिक योगदान इस पुनीत कार्य में डालना होगा। क्योंकि यह काम अत्यावश्यक है, इसलिये हम वेतन दिवस तक इसकी प्रतीक्षा नहीं कर सकते। आईये, हम क्यूबा की वीर जनता का क्रांतिकारी अभिवादन करें।

विश्व अर्थव्यवस्था

साथियो,

आइये, हम विकसित विश्व की अर्थव्यवस्था पर एक दृष्टि डालें। तथाकथित बाजार अर्थव्यवस्था के नारे के अंतर्गत उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली को सर्वग्रासी संकट का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन [ओ इ सी डी] द्वारा जारी अधोलिखित आंकड़े दर्शाते हैं कि इस समयावधि अर्थात् वर्ष 1990-94 में विशेष रूप से उस समय से जब वैश्वीकरण के झंडे तले संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था तभी से पूरे यूरोप, अमरीका तथा अन्य विकसित पूंजीवादी देशों की अर्थ व्यवस्थाओं को महान मंदे की स्थिति ने जकड़ रखा है। सकल घरेलू उत्पाद में कमी आई है, बेरोजगारी में वृद्धि हुई है और प्रत्येक देश में नये-नये रोजगारों के सर्जन की प्रक्रिया मंद हुई है।

औद्योगिक देशों का सकल घरेलू उत्पाद [प्रतिशत]

	86-90	91-94
जापान	4.2	4.0
अमरीका	2.4	2.1
कैनेडा	3.0	2.6
यूरोपीय समुदाय	3.2	1.8
इ एफ टी ए (फिनलैंड के अतिरिक्त)	2.2	0.8

औद्योगिक देशों में बेरोजगारी [प्रतिशत]

	1990	1994
अमरीका	5.8	6.2
कैनेडा	8.5	11.0
आस्ट्रिया	3.8	4.8

नार्वे	4.5	6.0
स्वीडन	1.8	7.8
स्विटजरलैंड	1.0	4.0
यूरोपीय समुदाय	9.0	12.1
जापान	2.0	3.0
युनाइटिड किंगडम	5.9	8.8
फ्रांस	9.0	12.2
इटली	11.6	12.1
पश्चिम जर्मनी	5.8	8.2
बेलजियम	9.0	13.0
डेनमार्क	9.5	12.2
नीदरलैंड	8.0	10.0
लग्जमबर्ग	1.8	2.8
युनान [ग्रीस]	7.0	11.0
स्पेन	17.0	24.0
पुर्तगाल	4.0	7.0
फिनलैंड	3.5	18.0

रोजगार सर्जन [प्रतिशत]

	86-90	91-94
जापान	1.5	0.8
अमरीका	1.8	1.2
कैनेडा	2.2	0.2
यूरोपीय समुदाय	1.5	0.3
इ एफ टी ए [फिनलैंड के अतिरिक्त]	0.9	1.3 [1.3 को कम करके]

[इ एफ टी ए देश: आस्ट्रिया, नार्वे, स्वीडन, स्विटजरलैंड तथा फिनलैंड इत्यादि]

ये आंकड़े अपनी कहानी स्वयं सुनाते हैं। मैं यहां रोजगार सर्जन की कमी और गरीबी में चौका देने वाली सीमा तक वृद्धि के प्रश्न को छेड़ना नहीं चाहता। तथापि एक बात तो स्पष्ट है कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप वस्तुओं के उत्पादन तथा सेवाओं के क्षेत्र में जो विशाल संभावनाएं उत्पन्न हुई थी उनका लाभ पूंजीवाद के मूल ढांचे के भीतर सामान्य रूप से जनता के जीवन को समृद्ध बनाने की दिशा में उठाया नहीं गया है। वास्तव में सभी प्रकार के विरोधाभ्यास तथा विवाद बढ़ते ही चले जा रहे हैं।

वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही असमानतातथा अल्प विकसित देशों के दरिद्रता की दलदल में और धंसते चले जाने की समस्याएं आज हमारी चिंता का प्रमुख कारण बनी हुई है। विकासशील देशों में उत्पादन के नये केंद्र बनने तथा आयातों के रोजगार नाशक प्रभावों के चलते यह चिंता औद्योगिक देशों में भी अनुभव की जा रही है। तर्क दिया जा रहा है कि अल्प-वेतन वाली अर्थव्यवस्थाओं से आयात के चलते प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही रूपों में रोजगार का विनाश होता है। प्रत्यक्ष रूप में इसलिये क्योंकि उत्पादन के स्थान में परिवर्तन हो जाता है और अप्रत्यक्ष रूप में इसलिये क्योंकि तकनीकी परिवर्तन होने से श्रमिक संख्या की बचत होती है। नयी प्रौद्योगिकी के तीव्र विस्तार से उल्लेखनीय संख्या में रोजगार समाप्त हो जाते हैं। पश्चिम प्रौद्योगिकी का अल्प वेतन वाली अर्थव्यवस्थाओं में अपविस्तार होना भी औद्योगिक उत्तर में बढ़ रही चिंता का एक कारण है इससे अल्प वेतन देने वाले उत्पादक न केवल अपराजित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ की स्थिति में आ जाएंगे अपितु इसका श्रम मानकों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इन्हीं चिंताओं ने औद्योगिक देशों में संरक्षणवादी कदम उठाने के रुझान को बल प्रदान किया है।

विकसित पूंजीपति देश तृतीय विश्व के देशों के अपने शोषण तथा उत्पीड़न में वृद्धि करने के लिये कदम उठा रहे हैं। वे अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा गैट जो अब विश्व व्यापार संगठन के रूप में परिवर्तित हो चुका है, का प्रयोग कर रहे हैं। तृतीय विश्व के देशों के ऊपर ऋण की सदाबहार वृद्धि के रूप में प्रतिबिम्बित हो रहा है। इसके कारण वे दिवालियापन की स्थिति में पहुंच चुके हैं। यह अंतिम संवृति मैक्सीकों के संकट में प्रतिबिम्बित हुई है। मैक्सिको अपने ऊपर लदे ऋण के भारी-भरकम बोझ को उतारने के चक्कर में दिवालिया हो गया था और उसकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था धाराशायी हो गयी है।

तृतीय विश्वेपर वर्ष 1993 में ऋण का कुल बोझ 177 अरब डालर था। यह और विकराल बनता चला जा रहा है। इसके फलस्वरूप प्रत्येक दूसरा देश ऋण के इस मकड़ ताल में फंस चुका है। बड़े विकसित देशों विशेष रूप से अमरीका जापान तथा जर्मनी द्वारा उन देशों से विशाल धन-राशि सोख ली जाती है। विश्व बैंक की सितंबर 1994 में जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1994 के पहले छह मास में सभी ऋणागस्त देशों से विशुद्ध 73.1० लाख अमरीकी डालर की राशि का निःस्राव हुआ था। रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नुस्ख का पालन करने वाले 26 में से 2० देश अपनी-अपनी अर्थव्यवस्थाओं में सुधार लाने में विफल रहे हैं। शेष 6 देशों की गरीबी का उन्मूलन करने में कम से कम तीस वर्ष लगेंगे।

विश्व बैंक/ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व व्यापार संगठन से तथाकथित वैश्वीकरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहायता देने की अपेक्षा रखी जाती थी किंतु व्यवहार में इसके ठीक विपरीत ये संगठन शक्तिशाली देशों विशेष रूप से विश्व की अत्यंत शक्तिशाली सैनिक एवं आर्थिक सत्ता अमरीका के पक्ष में काम कर रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन के अस्तित्व में आने पर भी व्यापार मुद्दों में बढ़ोतरी हो रही है। सबसे नयी घटना कार उद्योग के संबंध में अमरीका तथा जापान के मध्य गंभीर टकरावों से संबंध रखती है। अमरीका चाहता है कि जापान के कार-शो-रूम अमरीकी कारें बेचे अमरीकी हिस्सों-पुर्जों की खरीद और अधिक करें। जापान द्वारा

अमरीका के निदेशों का विरोध किया जा रहा है। अब वह जापान के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दे रहा है। उसे न विश्व व्यापार की संगठन की कोई चिंता है और न ही जापान की संप्रभुसत्ता की कोई परवाह है।

इसलिये ऊपर वर्णित तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि तथाकथित वैश्वीकरण एवं उदारीकरण को इस ढंग से संचालित किया जाता है जिससे विकसित पूंजीवादी देशों तथा शक्तिशाली राष्ट्रों के हितों की रक्षा हो सके। इसका और अधिक वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। साम्राज्यवादी दबावों के अंतर्गत वैश्वीकरण तथा उदारीकरण से पड़ने वाले प्रभावों से हम परिचित ही हैं और हम उनके विरोध में बड़े संघर्ष करने के लिये विवश हुए हैं।

साम्राज्यवादी आक्रमण

अमरीकी साम्राज्यवाद लोक जनवादी गणराज्य कोरिया के ऊपर दवाब डाल रहा है तथा प्रत्येक ढंग से उसका भयादोहन करने का प्रयास कर रहा है। वे लोग परमाणु सुरक्षा के नाम पर कोरिया के आंतरिक मामलों में निर्लज्ज हस्तक्षेप कर रहे हैं। अमरीका चाहता है कि लोक जनवादी गणराज्य कोरिया अपनी परमाणु ऊर्जा सुविधाओं को नष्ट कर दे। उसने इसके लिये सैन्य हस्तक्षेप और संयुक्त राष्ट्र द्वारा आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी है। चीन द्वारा घोर आपत्ति किये जाने के कारण उसके नये मनोरथ पूर्ण नहीं हो सके हैं। तथापि वे अभी भी कोरिया पर दबाव डालने की कार्रवाइयां कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि कोरिया-अमरीका के निदेशों के अनुसार काम करे किंतु कारिया की सरकार तथा जनता द्वारा दृढ़तापूर्वक अमरीका के इन हथकंडों का तीव्र प्रतिरोध किया जा रहा है। अत: दूसरा समाजवादी देश कोरिया भी अमरीका के आक्रमणों को झेल रहा है।

अमरीका विभिन्न ढंगों से चीन पर दबाव डाल रहा है ताकि वह अमरीकी मनोरथों का समर्थन करे और उनके लिये अपनी सहमति व्यक्त करें। चीन अमरीका के इन हथकंडों से परिचित [जागरूक] है और वह इनका प्रतिकार करने में सक्षम है।

इसी श्रृंखला में अमरीका का सबसे नया आक्रमण ईरान को धमकाना और उस पर व्यापार तथा आर्थिक संबंधों पर रोक लगाने की धमकियां देना है। वह उन देशों और विदेशी कंपनियों को धमकाने से भी झिझक नहीं दिखा रहा जो ईरान के साथ व्यापारिक संबंध बनाए हुए हैं। क्लिंटन प्रशासन ने पहले ही इस संबंध में आदेश जारी कर दिये हैं। इन आदेशों के अंतर्गत अमरीकी तेल कंपनियों पर तेल का पता लगाने के काम में ईरान के साथ सहयोग करने या उसका तेल खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसने ईरान को सैनिक कार्रवाई करने की धमकी भी दी है। यह धमकी इस आधार पर दी गई है कि ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में ऐसे अनेक द्वीपों पर अधिकार जमा लिया है जिन्हें अमरीका ने सुरक्षा प्रदान की थी।

निकट अतीत में उसके द्वारा उस समय उत्तेजक कार्रवाई की गई जब रूस तथा ईरान के मध्य परमाणु ऊर्जा उपकरणों तथा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के प्रश्न पर परस्पर सहमति हुई थी। रूस अमरीकी दबाव के आगे नहीं झुका। ईरान के राष्ट्रपति द्वारा पिछले दिन भारत की यात्रा की गई थी। अमरीका ने उसे पसंद नहीं किया है। उसके द्वारा ईरान के साथ सहयोग करने वाले देशों को दी जाने वाली धमकियां हम पर भी लागू होती है।

श्रमिक वर्ग पर आक्रमण

हम जानते हैं कि उदारीकरण की तथाकथित नीति के भाग के रूप में विश्व भर का और विशेष रूप से विकसित पूंजीवादी देशों के श्रमिक वर्ग पर गंभीर आक्रमण किये जा रहे हैं। इसका पहला शिकार रोजगार का स्थायित्व बना है; न केवल मालिकों अपितु सरकार द्वारा कल्याणकारी कदमों में कमी लाना इसका प्रमुख लक्षण बन चुका है। अमरीका सहित अनेक देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा इत्यादि कल्याणकारी मदों पर होने वाले खर्चों में कटौती की जा रही है। पिछले दिनों जापानी मालिकों द्वारा नये प्रकार के हमले शुरू किये गए हैं। जीवन भर के लिये रोजगार की व्यवस्था जो अब तक वहां जारी थी, को समाप्त कर दिया गया है। इसकी अपेक्षा समय-दर व्यवस्था, उत्पादन-आधारित वेतन व्यवस्था लागू की जा रही है। यह वेतनों में कटौती करने की नृशंस कार्रवाई है, कहने की आवश्यकता नहीं। इसके साथ-साथ रोजगार के अवसरों में भारी कमी की जा रही है।

जहां तक अमरीका का प्रश्न है, वहां अनेक उद्योगों में श्रमिकों पर वेतन कटौतियां लादी जा रही हैं। इसी प्रकार एयर लाइन्स श्रमिकों के मामले में भी दोहरी वेतन व्यवस्था लागू कर दी गई है। लगभग आधे पायलटों, अमले के सदस्यों जिनमें परिचारिकाएं भी शामिल हैं, के लिये 'बी' श्रेणी के वेतन लागू किये गये हैं। इस प्रकार उनके वेतनों में गंभीर कटौती की गई है।

जर्मनी तथा यूरोप के कुछ अन्य देशों में एक नये प्रकार की आक्रमण कार्रवाई शुरू की गयी है। पेंशन व्यवस्था का निजीकरण किया जा रहा है। राज्य द्वारा पेंशन देने के स्थान पर निजी कार्यक्रमों का प्रारंभ करने के लिये यह कदम उठाया गया है। श्रमिक इन निजी कार्यक्रमों के लिये अपना योगदान डालेंगे और इस प्रकार वे पेंशन की कुल राशि एकत्रित करेंगे। इस प्रकार संचित कोष निजी हाथों में रहेगा जिसे वे लोग अपने व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये मनमाने ढंग से प्रयुक्त कर सकेंगे। यह व्यवस्था अब फ्रांस, जर्मनी, इटली तथा यूरोप के अन्य छोटे देशों में लागू की जा रही है।

साथियो, मैं विश्व परिदृश्य पर और विस्तार में जाना नहीं चाहता। उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट हो जाता है कि पूंजीवादी व्यवस्था संकटग्रस्त है और वह कभी भी संकट मुक्त समाज का निर्माण नहीं कर सकती। संकट से मुक्ति पाने के नाम पर श्रमिक वर्ग को अलग करके उस पर आक्रमण किया जा रहा है। साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा आर्थिक, राजनीतिक तथा सैनिक अस्त्रों का प्रयोग करके दुर्बल राष्ट्रों का अमानवीय शोषण किया जा रहा है। इसलिये इसका केवल एक ही उत्तर है कि हम अपनी पूरी शक्ति जुटा कर प्रभावी ढंग से इस व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करें।

साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष का महत्व सर्वाधिक है।

साथियो, क्योंकि हमारे महासचिव ने विस्तार में राष्ट्रीय स्थिति पर प्रकाश डाला है, अत: मैं कुछ विशेष मुद्दों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने के अतिरिक्त और विस्तार में नहीं जाऊंगा।

कश्मीर

11 मई, 1995 की प्रभात बेला में सूफी संत शेख नूरुद्दीन नूरानी की 535 वर्ष पुरानी दरगाह [चरार ए शरीफ] को जला दिया गया। शेख नुरुद्दीन नूरानी की पावन स्मृति में बनाई गई यह दरगाह मुसलमानों के लिये केवल पूजास्थल ही नहीं था अपितु हिंदुओं सहित सभी समुदायों, समस्त कश्मीरियों तथा भारत एवं भारत से बाहर सभी स्थानों पर रहने वाले लोगों की आस्था एवं श्रद्धा का स्थल भी था। चरार ए शरीफ को अग्नि की भेंट कर देने का काम ठीक वैसा ही जघन्य कृत्य था जैसा भिण्डरांवाला गिरोह ने श्री हरि मंदिर साहेब पर अपना अधिकार जमा कर किया था या संघ परिवार द्वारा बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करके किया गया था। ये सभी कृत्य एक-समान घृणित थे। इसका उद्देश्य था देश की एकता तथा अखंडता को समाप्त करना। सांप्रदायिकता के साथ समझौता करने की कांग्रेस सरकार की नीति के चलते भिंडरांवाला गिरोह अमृतसर के पवित्र मंदिर को हस्तगत कर सका वहीं उसी नीति के कारण संघ परिवार बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने में सफल रहा था। चरार ए.शरीफ में भी कश्मीर प्रशासन तथा केंद्र में सत्तारुढ़ कांग्रेस सरकार द्वारा अपनी अकुशलता एवं अयोग्यता का प्रदर्शन किये जाने के कारण विनाशकारी परिणाम निकला था। अराजक तत्वों द्वारा मुसलमानों के मन-मस्तिष्क को विषाक्त बनाने के प्रयास किये गये और इस प्रकार वे देश तथा विदेश में यह प्रभाव देना चाहते थे कि भारत में मुसलमानों के पूजा स्थल सुरक्षित नहीं हैं। इस प्रकार आतंकवादी अपने जघन्य कृत्यों के लिये अंतर्राष्ट्रीय कठमुल्लावाद तथा देश में रहने वाले मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करना चाहते थे। यह एक गंभीर घटना है। इसकी तुलना केवल बाबरी मस्जिद के विध्वंस से ही की जा सकती है। जहां सरकार इस मामले में घपलेबाजी से काम ले रही है वहीं देशभक्त जनता का कर्त्तव्य बन जाता है कि वे ऐसी घटनाओं को देश में सांप्रदायिक-अवदाह [आग] का रूप न लेने दें।

भारत सरकार कश्मीर की स्थिति से निपटने में पूर्णतया विफल रही है। वे लोग अब भी इस मुद्दे को सैन्य बल तथा प्रशासकीय तंत्र की सहायता से सुलझाना चाहते हैं। यह वही प्रक्रिया है जिसका प्रयोग वर्षों से किया जा रहा है और यह प्रयोग गलत सिद्ध हो चुका है। इस समस्या का राजनीतिक समाधान निकाला जाना चाहिये जिसके अंतर्गत कश्मीरी जनता को अधिक स्वायत्ता दी जानी चाहिये ताकि वे भारतीय संघ में रहते हुए स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकें। अन्यथा चुनावों की बात करना व्यर्थ होगा।

बढ़ रहा सांप्रदायिक खतरा

बाबरी मस्जिद के मामले में भी भारत सरकार अभी तक समुचित कदम उठाने से इंकार कर रही है। क्योंकि भारत सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय को कार्यरूप देने के लिये कोई वादा करने से इंकार कर रही है, इसलिये बाबरी मस्जिद के प्रश्न पर संविधान की धारा-142 के अंतर्गत वह भी अपना निर्णय देने से इंकारी है। गृह मंत्री ने सार्वजनिक रूप से घोषित न्यायालय के निर्णय पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि बाबरी मस्जिद समस्या का समाधान ढूंढ निकालने का केवल एक ही मार्ग शेष और वह है संविधान की धारा 138[2] के अंतर्गत यह मामला उच्चतम न्यायालय को सौंप दिया जाए। किंतु सरकार ने अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। संघ परिवार ने एक बार फिर आक्रमक रुख अपना लिया है। वे कह रहे हैं कि वे अब 3००० मस्जिदों जिनमें मथुरा तथा काशी की मस्जिदें भी सम्मिलित हैं, को ध्वस्त करने की अपनी योजना को कार्यरूप देंगे।

निकट अतीत में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की नेता साध्वी रितम्बरा ने मध्य प्रदेश के जिला देवास में स्थित उदयनगर में यह घोषणा की थी, यदि एक भी हिंदु को ईसाई बनाया जाता है तो "किसी भी इसाई को यहां रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।" इस क्षेत्र में रहने वाले इसाई संघ गिरोह द्वारा एक नन [प्रचारिका] की हत्या किये जाने पर अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं। साध्वी रितम्बरा ने इसी संदर्भ में यह धमकी दी थी।

महाराष्ट्र में शिव सेना भाजपा गठधिन को विजय मिलने प्राप्त होने के पश्चात् स्थिति और खराब हो गई है। बम्बई शहर में बंगला देशी घुसपैठियों को बाहर भेजने के नाम पर मुसलमान जनता का जीवन खतरे में डाल दिया है और शिव सेना के गिरोहों ने उनके जीवन को दयनीय बना डाला है।

अत: धर्मनिरपेक्षता की नींव पर आधारित देश की एकता तथा अखंडता पर भारी दबाव पड़ रहे हैं। इसके साथ-साथ जातिवादी शक्तियां भी विशाल स्तर पर देश में बढ़ रही है। केवल राजनीतिक दलों को ही अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों या उच्च जातियों के नाम पर संगठित नहीं किया जा रहा अपितु ट्रेड यूनियनों के संगठन भी जाति के आधार पर बनाए जा रहे हैं।

इन परिस्थितियों में श्रमिक वर्ग की एकता खतरे में पड़ गई है। इसलिये, मैं नहीं समझता कि धार्मिक कठमुल्लावाद, जातिवाद तथा सांप्रदायिकता विरोधी संघर्ष के महत्व पर बल देने की कोई आवश्यकता है। स्वाभाविक रूप से सी आइ टी यू को इस संघर्ष में नेतृत्वकारी भूमिका का निर्वहन करना होगा।

देश संप्रभुता के साथ समझौता

हम जानते हैं कि सरकार की नीतियों तथा इस देश की प्रतिगामी राजनीतिक शक्तियों द्वारा अपनाई गढ नीतियों के परिणामस्वरूप देश की एकता तथा अखंडता खतरे में है। भारत सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियां जन विरोधी तथा राष्ट्रविरोधी हैं क्योंकि इन नीतियों के अंतर्गत अनेक ढंगों से उसने हमारी तथा राजनीतिक स्वतंत्रता के मूल्य पर समझौते कर लिये हैं। मैं यहां इसके विवरण में जाना नहीं चाहूंगा क्योंकि महासचिव की रिपोर्ट में इस प्रश्न पर विस्तृत चर्चा की गई है।

विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में, हमारी अर्थव्यवस्था के उन मूलभूत क्षेत्रों में जहां हमने विश्व स्तर पर

प्रतिस्पर्धात्मक श्रेष्ठता प्राप्त की थी, राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया जा रहा है। विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नीति में इसी बात पर बल दिया जा रहा है कि किसी न किसी प्रकार इन क्षेत्रों में उनका अधिनायकत्व स्थापित हो जाए। वह चाहे इनमें उनकी तथाकथित 'भागीदारी' से हो या उनका पूर्ण विनाश करके हो ताकि इन मामलों में उन पर भारत की निर्भरता निरंतर बनी रहे। यह काम ऊर्जा क्षेत्र तेल, कोयला तथा विद्युत; कैपिटल गुड्स क्षेत्रों लौह तथा इस्पा, एवं भारी इंजीनियरिंग इत्यादि में पहले ही किया जा रहा है। दूरसंचार क्षेत्र बैकिंग तथा बीमा को उनके लिये खोला जा रहा है।

देश के बड़े पूंजीपति इन नीतियों की भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे हैं- क्योंकि इन्हीं नीतियों के चलते वे भारी-भरकम लाभ अर्जित करने तथा सार्वजनिक क्षेत्र में संचित जनता के धन को हड़पने की स्थिति में आ गये हैं। तथापि उनमें से कुछ लोगों [पूंजीपतियों] के लिये इन नीतियों के अनेक पक्षों का समर्थन कर पाना कठिन हो रहा है।

सदाव्रत मूल्य वृद्धि, उच्च स्थानों पर भ्रष्टाचार, और पूर्व की अपेक्षा ऋण का भारी बोझ, बेरोजगारी में चौंका देने वाली सीमा तक वृद्धि-कामबंदी तथा श्रमिक वर्ग की चिंता के प्रधान कारण है।

हमारी सब नयी चिंता का एक विषम प्रतिरक्षा क्षेत्र में सरकार का रुख है। अमरीका के साथ सहयोग करने के नाम पर हमारी रक्षा क्षमताओं के स्वतंत्र विकास को अवरुद्ध किया जा रहा है। यह एक अक्षम्य अपराध है। अभी निकट अतीत में हमारे रक्षा राज्य मंत्री श्री मलिकार्जुन ने अमरीका के प्रतिरक्षा मंत्री श्री विलयिम पेरी के साथ रक्षा सहयोग के मामले में 12 जनवरी को एक समझौते पर हस्ताक्षर किये थे। अमरीका का प्रयास था कि वह भारत को भी अपने भूमण्डलीय प्रतिरक्षा नेटवर्क में सम्मिलित कर ले जिस पर निःसंदेह उसका ही अधिनायकत्व है। "भारत तथा अमरीका के मध्य प्रतिरक्षा सहयोग पर तथाकथित सहमति पत्र" कहता है कि इस प्रतिरक्षा सहयोग के अतर्गत नागरिक सहयोग और "रक्षा उत्पादन एवं शोध" को भी सम्मिलित किया जाएगा।

हम जानते हैं कि अमरीका ने हमारी उपग्रह परियोजनाओं के लिये रूस से क्रायोजनिक इंजनों की आपूर्ति के मामले में हमारे साथ कैसा व्यवहार किया था। अमरीका के दबाव पर रूस अनुबंध से पीछे हट गया है और उसने इंजनों की आपूर्ति करने से इंकार कर दिया है और हमें अपने बल पर ही इस मामले में आगे की कार्रवाई करनी पड़ी थी।

लो-कम्बैट एयर क्राफट [एल सी ए] के मामले में यद्यपि दोनों देशों के मध्य तकनीकी सहयोग समझौता हुआ था तथापि अमरीका ने बहुत कम सहयोग दिया और हमें अपने ही बल पर यह काम करना पड़ा था। हम वर्षांत तक इस कार्य का निष्पादन कर सकेंगे। यह सूचना मिली थी कि सरकार अमरीकी दबाव में आकर हमारे मिसाइल कार्यक्रम की गति को कम कर रही है। प्रधानमंत्री ने संसद में इस बात से 'इंकार' किया है। तथ्य तो यह है कि तथाकथित उदारीकृत वातावरण के अंतर्गत रक्षा शोध एवं विकास कार्यों को ठप्प किया जा रहा है। रक्षा शोध "अमरीका से कम लागत पर" प्राप्त किया जाएगा। सभी गंभीर एवं निर्णायक अवसरों पर अमरीका हमारे विपक्ष में रहा है। वर्तमान में भी वह पाकिस्तान को अत्यंत आधुनिक शस्त्रों की आपूर्ति कर रहा है और अमरीका के साथ सहयोग करने का दुष्परिणाम हमारे स्वतंत्र रक्षा विकास कार्यों को तारपीडो करने के रूप में निकालेगा। प्रत्येक देशभक्त भारतीय को इसका विरोध करना ही चाहिये।

सी आइ टी यू अन्य ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर इन नीतियों के विरुद्ध गंभीर संघर्ष करती रही है। उसने जनता के अन्य वर्गों को भी इस संघर्ष के लिये लामबंद किया है तथा उसका सहयोग प्राप्त किया है। इससे बड़ी सीमा तक सरकारी नीतियों की पोल खोली जा सकी है। किंतु हम कुछ सीमा तक इन नीतियों की गति की विपरीत मोड देने में सफल रहे हैं। इसलिये एक बार पुनः हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम इस आंदोलन को और सुदृढ़ बनाएं और नीतियों को बदलं। इसके लिये हमें सतत एवं श्रम साध्य प्रयास करेंगे।

कांग्रेस [ई] संकट में

कुछ मास पूर्व हुए विधान सभा चुनावों में जनता ने कांग्रेस-इ को भारी झटके दिये हैं। उसे पिछले नवंबर के चुनावों में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा सिक्म में पराजय का मुंह देखना पड़ा है। वे उड़ीसा में इसलिये जीत सके क्योंकि वहां का मुख्य मंत्री तथा जनता दल नेता नयी आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन के मामले में कांग्रेस-इ की अपेक्षा अधिक मुखर थे। फरवरी में संपन्न विधान सभा चुनावों के अगले चरण में भी कांग्रेस-इ को गंभीर झटके झेलने पड़े हैं। भारत के प्रमुख औद्योगिक राज्य महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी-शिव सेना गठबंधन सत्ता प्राप्त करने में सफल रहा जबकि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत प्राप्त कर लिया है। किंतु बिहार में कांग्रेस द्वारा अने जघन्य कार्रवाइयां किये जाने पर भी लालू प्रसाद यादव न केवल चुने गए हैं अपितु उन्होंने राज्य विधानसभा में भी अपना बहुमत बढ़ा लिया है। कांग्रेस-इ की पराजय का वर्तमान चरण उसकी जन विरोधी नीतियों पर एक गंभीर प्रहार है। जहां कहीं भी जीवंत [शक्तिशाली] लोकतांत्रिक विकल्प जनता को मिला, उसने उसे ही सत्ता के घोड़े पर सवार कर दिया। महाराष्ट्र तथा गुजरात में शिव सेना-भाजपा गठबंधन तथा भारतीय जनता पार्टी को इसलिये बहुमत प्राप्त हो सका क्योंकि वहां वाम तथा जनवादी शक्तियां दुर्बल थीं। इस चुनावी-निर्णयादेश के कारण देश में एक नयी राजनीतिक स्थिति उभरी है। जहां उसने [जनता] कांग्रेस-इ को लगभग ठुकरा ही दिया है वहीं घोर प्रतिक्रियावादी दलों महाराष्ट्र में शिव सेना-भाजपा गठबंधन तथा गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को चुन लिया है।

इन चुनावों के पश्चात् कांग्रेस-इ में गंभीर विखंडन हुआ है जिसकी परिणति कांग्रेस नेताओं के बड़े भाग द्वारा अंतिम रूप से कांग्रेस के साथ अपने संबंध विच्छेद करने के रूप में निकला है। पिछले मास 19 तारीख को नयी दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हुआ। उन्होंने अपनी पार्टी के नये अध्यक्ष तथा पदाधिकारियों का चुनाव किया। उन्होंने दावा किया है कि वे ही वास्तविक [असली] कांग्रेस है और इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की आलोचना की है।

सत्तारूढ़ दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा है। देश के ग्यारह राज्यों में वह सत्ता खो चुकी है। इसके साथ ही वह फूट का शिकार बनी हुई है। इसलिये उनके पास सत्ता में बने रहने के लिये कोई नैतिक अधिकार नहीं रहता। ठीक बात तो यही होगी कि श्री राव स्वयं ही पद त्याग कर दें और नये चुनावों का सामना करें।

महाराष्ट्र में शिव सेना-भाजपा गठबंधन तथा गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आ जाने से सांप्रदायिक शक्तियां और सुदृढ़ हुई है। वे और शक्ति के साथ केंद्र में सत्तारूढ़ होने की अपनी नीति का अनुपालन कर रही है। इन परिस्थितियों में श्रमिक वर्ग को निर्णायक भूमिका निभानी होगी। उसे कांग्रेस तथा भाजपा एवं शिव सेना जैसे प्रतिगामी सांप्रदायिक दलों को परास्त करने के लिये जनवादी शक्तियों को सुदृढ़तर करना होगा।

संगठन को सुदृढ़ बनाना

साथियो, संभाषण समाप्त करने से पूर्व मैं आपका ध्यान विशेष संगठनात्मक मामलों की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। सरकार की प्रतिगामी नीतियों के विरुद्ध सतत् संघर्ष करने तथा श्रमिक वर्ग की दैनंदिन मांगों की पूर्ति के लिये संघर्ष करने की नीति के फलस्वरूप भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र [सी आइ टी यू] की प्रतिष्ठा बढ़ती ही चली जा रही है। इससे श्रमिक वर्ग में हमारे लिये अत्याधिक सहानुभूति उत्पन्न हुई है। किंतु यह तथ्य हमारी सांगठनिक शक्ति से प्रतिबिम्बित नहीं होता क्योंकि हम श्रमिकों के नये-नये वर्गों को अपनी पंक्तियों में खींच लाने के मामले में पिछड़ रहे हैं। अपनी सांगठनिक शक्ति को बढ़ाए बिना हम वह भूमिका नहीं निभा सकते जो हमें निभानी चाहिये। सी आइ टी यू अन्य श्रमिक संगठनों की भांति मात्र एक ट्रेड यूनियन संगठन ही नहीं है अपितु यह एक ऐसा संगठन है जिसने पूरे वर्ग को लामबंद करने तथा संपूर्ण श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा करने के काम में अग्रणी भूमिका निभानी है। यह एक बहुत बड़ा काम है। किंतु यह काम हमें करना ही होगा।

हमारे द्वारा पारित संगठनात्मक रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से हमारी दुर्बलताओं तथा शक्ति को रेखांकित किया गया है। हमारी दूर्बलताओं को दूर करने के लिये रिपोर्ट में मार्गदर्शन दिया गया है। सी आइ टी यू के सभी नेताओं तथा कार्यकर्ताओं का यह काम अत्यंत गंभीरतापूर्वक करना होगा। इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते।

सी आइ टी यू ही ऐसा एकमात्र संगठन है जो ट्रेड यूनियनों का परिसंघ बनाने के महत्व पर बल देता रहा है। संयुक्त संघर्षों के अनुभवों तथा सत्तारूढ़ पार्टी के हमले जारी रहने के कारण ट्रेड यूनियन एकता की संभावनाओं में अपार वृद्धि हुई है। अनेक संयुक्त संघर्षों के नये-नये अनुभवों के दृष्टिगत आधार [निचले] स्तर पर संगठनात्मक संबद्धता की इच्छा प्रबल हुई है कार्यकर्ताओं की और से एकता के लिये दबाव बढ़ रहा है और कोई भी ट्रेड यूनियन केंद्र इस संबंध में नकारात्मक रुख अपना नहीं सकता है। सभी स्तरों पर एकता स्थापित करने तथा सांगठनिक शक्ति को और विशाल बनाने के लिये सभी स्तरों पर कैसे कदम उठाए जाएं। इसे देखना हमारी ट्रेड यूनियनों तथा नेतृत्व का कर्त्तव्य बन जाता है।

ट्रेड यूनियनों की मान्यता के प्रश्न पर निकट अतीत में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय खाद्य निगम कर्मचारियों के मामले में अभूतपूर्व निर्णय दिया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि ट्रेड यूनियनों की मान्यता के लिये गुप्त मतदान की पद्धति को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये और इस उद्देश्य के लिये उसने चुनाव की एक प्रक्रिया भी सुझाई है। इसलिये सी आइ टी यू को पूरी शक्ति के साथ गुप्त मतदान के माध्यम से ट्रेड यूनियनों की मान्यता की स्वीकृति के लिये संघर्ष चलाना होगा। साथियो, मैं एक बार पुनः आपको सी आइ टी यू संविधान का स्मरण दिलाना चाहूंगा। इस संविधान में ट्रेड यूनियनों की लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली को अत्याधिक महत्व दिया गया है। इसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया में अल्पसंख्या के विचारों को सम्मान देने तथा संचित मतदान प्रणाली अपना कर यूनियन के नेतृत्व में अल्पसंख्या को समाहित करने की बात कही गयी है। इसका सार रूप यह है कि ट्रेड यूनियनें श्रमिकों का प्राथमिक संगठन होती हैं जिसके माध्यम से वे मालिकों से अपने हितों की रक्षा करने के लिये संघर्ष करते हैं। यदि सभी श्रमिक एक ही संगठन में एकजुट होते हैं तो वह प्रभावी होगी। वर्तमान में विभिन्न कारणों से राजनीतिक या अन्य, यह व्यवस्था नहीं रही है। तथापि हमें प्रत्येक मामले का विशेष रूप से अनुशीलन करना होगा और आधार स्तर पर एकता को बहाली के लिये कदम उठाने होंगे।

साथियो,

इस वर्ष क्योंकि सी आइ टी यू की रजत जयंति है, इसलिये हमें सी आइ टी यू को सुदृढ बनाने के काम को विशेष कार्य के रूप में अपने हाथ में लेना चाहिये। सरकार की नीतियों के विरुद्ध एकीकृत संघर्षों को सशक्त एवं सुदृढ बनाना होगा और श्रमिकों के विरुद्ध होने वाले आक्रमणों का मुंहतोड़ प्रत्युत्तर देना होगा तथा उनकी दिशा को बदल देना होगा। आईये, हम प्रण करें कि हम अपनी एकता को सुदृढ़ बनाएंगे तथा सत्ताधारी वर्ग की प्रतिगामी नीतियों को परास्त करने के लिये संघर्ष करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपका क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं।

-ट्रेड यूनियन एकता अमर रहे- □

सम्पादकीय..

(पृष्ठ 1 का शेष)

इसी पृष्ठभूमि में दूरसंचार कर्मचारी तथा उनके तीन महासंघ एन एफ टी इ, एफ एन टी ओ तथा बी टी इ एफ सभी ट्रेड यूनियनों, अन्य जन संगठनों तथा जनता के लोकतांत्रिक एवं देश भक्त वर्गों की ओर से हार्दिक बधाई प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हैं। उन्होंने अपनी एकजुटता तथा दृढ़ संघर्ष करके इस अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र को बहुराष्ट्रीयों को सौंपने के मार्ग में चलने से सरकार को रोका है या रुकने पर विवश किया है। इस हड़ताल से अन्य सभी औद्योगिक महासंघों तथा सम्पूर्ण भारतीय श्रमिक वर्ग में नये उत्साह का संचार होगा। ट्रेड यूनियन एकता और सुदृढ़ होगी और जब तक राष्ट्रहित में सरकार अपनी आर्थिक नीतियों का परित्याग नहीं कर देती तब तक इसके विरोध में चलने वाले संघर्षों को और तेज करने में सहायता मिलेगी। □